उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–402–औ0सं0/2019–19(125)ए0एस0/01 दिनांक 21 फरवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के द्वारा बाहरी व्यक्तियों की विद्युतीय दुर्घटना में मृत्यु की दशा में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–4004–औ0सं0 /2018–19(125)ए0एस0/2001 दिनांक 06.10.2018 (प्रतिलिपि संलग्न) में प्रभावी आदेशों में दी गयी क्षतिपूर्ति का प्राविधान है, परन्तु क्षतिपूर्ति के स्वीकृत हेतु प्रक्रिया पूर्ण करने में विलम्ब होने के कारण प्रभावित व्यक्ति/ परिवार को अनुमन्य क्षतिपूर्ति के भुगतान में विलम्ब होता है।

कारपोरेशन द्वारा क्षतिपूर्ति के विलम्ब को दृष्टिगत करते हुए क्षतिपूर्ति स्वीकृत की प्रक्रिया के सरलीकरण करने का निर्णय लिया जाता है। अतः बाहरी व्यक्तियों की घातक विद्युतीय दुर्घटना में मृत्यु होने पर जाँच की प्रक्रिया एवं क्षतिपूर्ति समय से न मिल पाने के कारण निम्नवत् समय सीमा एवं क्षतिपूर्ति स्वीकृत की प्रक्रिया एतद्द्वारा निर्धारित की जाती है :–

1. विद्युत अधिनियम 2003 के प्राविधानों के अनुसार बाहरी व्यक्तियों की विद्युतीय दुर्घटना होने पर उपखण्ड अधिकारी 24 घण्टे में दूरभाष पर एवं 48 घण्टे के अन्दर विद्युत दुर्घटना की सूचना निर्धारित प्रपत्र सं0–44(ए) पर सहायक निदेशक/उप निदेशक/निदेशक विद्युत सुरक्षा को सूचित करेंगे। इसके अतिरिक्त विद्युत दुर्घटना की सूचना जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन एवं निकटतम् चिकित्सालय को करेगा तथा कारपोरेशन के उच्च अधिकारियों को भी संज्ञानित करेगा।

2. विद्युत दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर सहायक निदेशक/उप निदेशक/निदेशक, विद्युत सुरक्षा द्वारा स्थलीय जाँच 18 दिनों में पूर्ण कर जाँच आख्या सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता को उपलब्ध करायेंगे।

3. इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता क्षतिपूर्ति स्वीकृति करने हेतु सक्षम अधिकारी होंगे, जिसके द्वारा निम्न प्रक्रिया का पालन किया जायेगा :–
   - I. विद्युत दुर्घटना की निदेशक, विद्युत सुरक्षा से रिपोर्ट प्राप्त होने पर पीड़ित परिवार के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों/अभिलेखों को संकलित करेगा।
   - II. प्राप्त आवेदन के अनुसार उत्तराधिकारी की सूचना मण्डल कार्यालय सहित सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय में चस्पा करेगें जिसमें आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु 07 दिन का समय दिया जायेगा।
   - III. उत्तराधिकारी का निर्धारण हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में दी गई व्यवस्था को संज्ञान में रखते हुये किया जायेगा। क्षतिपूर्ति की पात्रता का निर्धारण उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या–बी–3–151/दस–80–15(1)/78–प्र0को0 दिनांक 24 जनवरी, 1980 एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0 2018–औस/2012–27–एफ0/80 दि0 05.07.2012 (प्रतिलिपि संलग्न) में दी गयी परिवार/कुटुम्ब की परिभाषा के अनुसार किया जायेगा। उक्त शासनादेश अथवा कार्यालय ज्ञाप के तहत बाहरी व्यक्तियों की विद्युतीय दुर्घटना में मृत्यु की दशा में मृतक आश्रित के अधीन किसी भी प्रकार का सेवायोजन अथवा अन्य अनुतोष अनुमन्य नही होंगे।
   - IV. समयावधि समाप्त होने पर 07 दिन के अन्दर उत्तराधिकारी से उनका वोटर आई डी/पैन कार्ड/राशन कार्ड/पास पोर्ट/लेखपाल/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त कुटुम्ब रजिस्टर के आधार पर पीड़ित परिवार के उत्तराधिकारी का निर्धारण विधिक मापदण्डों के आधार पर करते हुये प्रकरण में क्षतिपूर्ति स्वीकृति का कारण आदेश में लिखित रूप से अंकित (Recording reason in writing) करते हुये आदेश निर्गत करेंगे। स्वीकृत आदेश की प्रति क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता को प्रेषित करेंगे।

4. उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विधिक रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जाये।

5. क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त करने वाले को अन्डरटेकिंग देनी होगी कि यदि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होगा तो उक्त धनराशि विभाग को वापस करेंगे और अगर तथ्य गलत पाये गये तो विधिक कार्यवाही भी करेंगे।

6. क्षतिपूर्ति भुगतान की सम्पूर्ण प्रक्रिया में 45 दिनों में पूर्ण कर ली जायें। मुख्य अभियन्ता (वितरण), विद्युत दुर्घटनाओं के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति के प्रकरणों का मासिक आधार पर अनुश्रवण करेंगे एवं भुगतान से सम्बन्धित समस्त सूचनायें क्षेत्रीय कार्यालय में संरक्षित रखेंगे एवं मासिक रिपोर्ट प्रबन्ध निदेशक, डिस्काम को भेजेंगे।

संलग्नकः– यथोपरि।

अध्यक्ष

संख्या–402–औ0सं0/2019, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/(वितरण)/(वित्त)/(कारपोरेट प्लानिंग)/ (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा एवं केस्को–कानपुर।
6. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश से सभी सम्बन्धित अधिकारियों को संज्ञानित कराते हुये अनुपालन सुनिश्चित कराये।
7. अधिशासी अभियन्ता (वेब) कक्ष सं0–407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड करने हेतु।

संलग्नकः– यथोपरि।

Aparna. U. 21/2/19.
(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–4004–औ0सं0/2018/19(125)ए0एस0/2001 दिनांक 06 अक्टूबर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक मण्डल की दिनांक 03.10.2018 को परिचालन के माध्यम से सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार याचिका सं0–10191/2009 (रिट सी) श्री शिव रंशू छुनेजा बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 10.04.2018 को पारित निर्णय के अनुपालन में विद्युतीय दुर्घटना में मृत एवं घायल बाहरी व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत आदेशों को अतिक्रमित करते हुये एतदद्वारा निम्न व्यवस्था प्रतिपादित की जाती है :–

1. कारपोरेशन के त्रुटिपूर्ण विद्युतीय अधिष्ठापन के कारण हुई बाहरी व्यक्तियों की विद्युतीय दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों व अन्य को क्षतिपूर्ति/मुआवजा दिये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के कार्यालय आदेश सं0–1011/चौबीस–पी–3–2018 दिनांक 01.05.2018 द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट अर्द्ध शा0प0सं0–2061–औ0सं0/2018–19(125) ए0एस0/01 दिनांक 09.07.2018 (अनुलग्नक–1) को कारपोरेशन में लागू किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।

2. विद्युत दुर्घटना में मृत्यु होने पर कारपोरेशन के आदेश सं0–4095–औ0सं0/2016–19(125)/ए0एस0/2001 दिनांक 13.10.2016 के निहित प्राविधानो के अन्तर्गत रू0 5.00 लाख अनुग्रह धनराशि का प्राविधान है। समिति की संस्तुतियों के अनुसार मृतक की आयु के सापेक्ष यदि किसी व्यक्ति की गणना के अनुसार क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 5.00 लाख से कम होने पर सम्बन्धित मृतक के आश्रितों को न्यूनतम रू0 5.00 लाख की क्षतिपूर्ति अनुमन्य की जाये।

3. घातक/अघातक विद्युत दुर्घटना में मृत्यु होने, स्थाई पूर्ण अपंगता होने तथा आंशिक अपंगता होने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की विवाहित/अविवाहित स्थिति, आयु एवं परिवार की संख्या के आधार पर समिति की रिपोर्ट (अनुलग्नक–1) में दी गई सारणियों के अनुसार अनुमन्य किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. समिति द्वारा अघातक विद्युत दुर्घटनाओं में कारपोरेशन के अधिष्ठान की त्रुटि न होने की स्थिति में **No fault liabilitty** के रूप में अनुग्रह धनराशि की क्षतिपूर्ति का अनुमोदन प्रदान किया गया।

5. आदेश सं0–4095 दिनांक 13.10.2016 में पशुओं की दुर्घटना में मृत्यु होने के सम्बन्ध में अनुग्रह धनराशि एवं अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

6. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्नक :– यथोपरि।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–4004–औ0सं0/2018, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा/केस्को, कानपुर।

5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन), उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
13. समस्त उप सचिव/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट **www.uppcl.org** पर अपलोड करने हेतु।
16. कट फाइल/पत्रावली संख्या–8–एम/92।

Pkumar

(प्रदीप कुमार)
डप महाप्रबन्धक (औ0सं0)

(5)

आ-सं-4004 6.10.18
का संलग्नक

(1)

अमित गुप्ता
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

UP POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
UP
UPPTCL

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग
लखनऊ – 226001
☎ : 0522–2287874/2218714
(फैक्स) : 0522–2287885

अर्द्ध शा0प0सं0–2061–औ0सं0/2018–19(125)–ए0एस0/01 दिनांक 09 जुलाई, 2018
31-47

विषय : विद्युतीय दुर्घटना में प्रभावित बाहरी व्यक्तियों व अन्य को क्षतिपूर्ति/मुआवजा दिये जाने हेतु नीति निर्धारण विषयक।

महोदय,

कृपया शासन के अर्द्ध शा0प0सं0–1333/चौबीस–पी–3/2018 दिनांक 25 जून, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कि सिविल रिट याचिका संख्या–10191/2009(रिट सी) शिव रामसू छूनेजा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.04.2018 के अनुपालन में विद्युत दुर्घटनाओं से प्राभावित व्यक्तियों व अन्य को क्षतिपूर्ति/मुआवजा दिये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्धारित करने के सम्बन्ध में शासन के कार्यालय आदेश सं0–1011/चौबीस–पी–3–2018 दिनांक 11 मई, 2018 के द्वारा गठित समिति की संस्तुतियाँ/रिपोर्ट प्रेषित करने से सम्बन्धित है।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर अपनी संस्तुतियाँ/रिपोर्ट तैयार की गई है जो कि मूलरूप में सलंग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

भवनिष्ठ,

(अमित गुप्ता)

श्री आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव (ऊर्जा),
उ0प्र0 शासन, बापू भवन,
लखनऊ।

Speed post

आ. सं. 4004 औ सं/18 6.10.18
का संलग्नक

Preface

Death or disability is irreparable loss to the family of the victims of accidents and cannot be compensated in terms of money for mental agony, loss of love & affection, protection of kith & kin etc. However, compensation supports family monetarily and that may prove a good helping hand to the victim. On the one side as well as his/her family compensation ought not to be excessive as this makes financial burden on exchequer while on another side, the compensation ought not to be so less as family suffers a lot. Compensation should be at least for such amount which may put back victim/victim's family in such pecuniary situation as if accident would have not been occurred. A reasonable compensation makes balance on both sides.

In order to find out fair and reasonable compensation Committee studied and discussed various methods of compensation in different departments like Railways, Roadways, Governments ex-gratia help in Natural disaster cases, as well as Act such as The Fatal Accidents Act 1855, The Public Liability Insurance Act 1991 etc. Above mentioned all compensation schemes are found to be based on no fault liability. (i.e. in which fault of any party need not to be proved). Committee also considered The Uttar Pradesh Motor Vehicle (Eleventh Amendment) Rules, 2011.

For that purpose the Committee worked out on fixation of notional income. The Committee considered Minimum Wages Act 1948 and Mahatma Gandhi National Rojgar Guarantee of 100 days work, but it is not sufficient for a person to fulfill expenses of a family. Currently, Minimum Wages Act prescribes from Rs. 292.82 to Rs. 360.81 per day. Considering all above factors Committee find it Rs. 51,000 per annum to be appropriate for notional income.

In the light of observations made in the judgment passed by the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad in Writ-C No. 10191 of 2009 and in order to provide fair and reasonable compensation to the victims of third party electrocution resulting in death, disablement, and injury cases on the basis of fault liability (i.e. on the report of Electrical Inspector of Vidyut Suraksha Nidesalaya), following guide lines are being recommended. The Committee also recommends suppression of Office Memorandum no. 4095-I.R./2016-19(125)A.S./2001 Dated 13.08.2016 and No. 2745-I.R./2016-19(125)A.S./2001 Dated 02.07.2016 ~~regarding~~ to the extent of human death and grievous injury cases respectively.

GUIDE LINES FOR COMPENSATION ON ELECTROCUTION

FAULT LIABILITY

A-Fatal Accident

1. Notional Income (N.I.) of victim shall be taken in to consideration as Rs. 51,000 (Fifty One Thousand) per annum (about Rs. 140 per day).
2. Multiplier shall be adopted as per following chart-

Age of Victim	Multiplier Applied (M.A.)
Up to 15 years	15
Above 15 years but not exceeding 20 years	16
Above 20 years but not exceeding 25 years	17
Above 25 years but not exceeding 30 years	18
Above 30 years but not exceeding 35 years	17
Above 35 years but not exceeding 40 years	16
Above 40 years but not exceeding 45 years	15
Above 45 years but not exceeding 50 years	13
Above 50 years but not exceeding 55 years	11
Above 55 years but not exceeding 60 years	8
Above 60 years but not exceeding 65 years	6
Above 65 years	5

3. The amount of compensation so arrived at in the case of fatal accident claims shall be deducted towards Personal and living Expenses (P.E.) by
   (i) 1/2[nd] if deceased was unmarried but if family of a bachelor is large and dependent on the income of the deceased, the deduction shall be 1/3[rd] (33.33%)
   (ii) 1/3[rd] if deceased was married where dependent family members are 2 to 3 in number, 1/4[th] where dependent family members 4 to 6 in number and 1/5[th] where dependent family members are more than 6 in number.
   (iii) For the purpose of calculation of number of family members in clause (ii), a minor dependent will be counted as half.

   Spouse, parents and grand-parents having no income and minor children shall be deemed dependent family members. (Parivar Register and affidavit may be considered as proof of family members and dependency).
4. The following General Damages shall also be payable in addition to Compensation Outlined (C.O.) above:

आ. सं 4004 6.10.18

(i) Compensation for Loss of Estate (L.E.) Rs. 5,000 (Five Thousand).
(ii) Compensation for Loss of Consortium (L.C.), if beneficiary is spouse Rs. 5,000 (Five Thousand).
(iii) Compensation for Loss of love and Affection (L.A.) Rs. 5,000 (Five Thousand).
(iv) Funeral Expenses costs of transportation of body (F.E.) Rs. 5,000 (Five Thousand) or actual expenses whichever is less.
(v) Medical Expenses (M.E.) –Actual expenses incurred before death supported by bills/vouchers but not exceeding Rs. 20,000 (Twenty Thousand).

Formula: N.I.×M.A.= C.O.

C.O. P.E.= Amount

C.O.-Amount+L.E.+L.C.+L.A.+F.E.+M.E.

= Total Compensation

Example for spot death of a person aged 14 years leaving behind mother and father:

51000×15=765000
765000÷3=255000
765000-255000+5000+5000+5000= 525000

B- Non-Fatal

General Damages in case of Injuries and Disabilities:

(i) Pain and Suffering
(a) Grievous injuries (G.I.) -- Rs. 10,000/-
(b) Simple injuries (S.I.) -- Rs. 5,000/-
(ii) Medical Expenses (M.E.) --Actual expenses incurred supported by bills/vouchers but not exceeding – Rs. 20,000 for grievous injury and – Rs. 10,000 for simple injury (on medical report)

Disability in non-fatal accidents:

The following compensation shall be payable in cases of disabilities to the victim arising out of non-fatal accidents:

A- Temporary Disability

आ॰सं॰ 4004 आरक्षित/18 6.10.18 (5) 4

Loss of income, if any, for actual period of disablement not exceeding fifty two weeks.

B- Permanent Disability

(a) In case of permanent total disablement the amount payable shall be arrived at by multiplying the annual loss of income by the Multiplier applicable to the age on the date of determining the compensation, or

(b) In case of permanent partial disablement such percentage of compensation, which would have been payable in the case of permanent total disablement as specified under item (a) above.

Injuries deemed to result in Permanent Total Disablement/Permanent Partial Disablement and percentage of loss of earning capacity shall be as per Schedule I under Workmen's Compensation Act, 1923, Disability Certificate from Medical Board mentioning percentage of disablement shall be final and shall be taken in to consideration.

Notional Income of victim shall be taken in to consideration as Rs. 51,000 (Fifty One Thousand) per annum.

Example for 100% permanent disability of person aged 14 years with medical bills for amount Rs. 20,000 (Twenty Thousand):

51000×15=765000
765000×100÷100=765000
765000+10000+20000=**795000**

No Fault Liability

1. In death --- Rs. 1,000,00 (One Lac)
2. In permanent disability --- Rs. 1,25,000 (One Lac and Twenty Five Thousand)
3. Grievous injury --- Rs. 3000 (~~Eight~~ Three Thousand)
4. Simple injury --- Rs. 2000 (~~Three~~ Two Thousand)

-- No compensation shall be paid if victim was involved in illegal activities like theft of electricity or riots etc.

--Compensation shall be decided by a Committee of concerned Superintendent Engineer and Executive Engineer within one month from the date of the accident.

--Third party insurance system may also be introduced to meet out compensation.

30/8/18

AGE OF VICTIM	MULTIPLIER	Compensation in case of death on basis of fault in Rupees				
		Unmarried deceased	If family of bachelor deceased is large and dependent on the income of deceased	Married deceased and dependent family members are 2 to 3	Married deceased and dependent family members are 4 to 6	Married deceased and dependent family members are more than 6
		2	3	4	4	5
Up to 15 yrs.	15	397500	525000	525000	588750	627000
Above 15 yrs. but not exceeding 20 yrs.	16	423000	559000	559000	627000	667800
Above 20 yrs. but not exceeding 25 yrs.	17	448500	593000	593000	665250	708600
Above 25 yrs. but not exceeding 30 yrs.	18	474000	627000	627000	703500	749400
Above 30 yrs. but not exceeding 35 yrs.	17	448500	593000	593000	665250	708600
Above 35 yrs. but not exceeding 40 yrs.	16	423000	559000	559000	627000	667800
Above 40 yrs. but not exceeding 45 yrs.	15	397500	525000	525000	588750	627000
Above 45 yrs. but not exceeding 50 yrs.	13	346500	457000	457000	512250	545400
Above 50 yrs. but not exceeding 55 yrs.	11	295500	389000	389000	435750	463800
Above 55 yrs. but not exceeding 60 yrs.	8	219000	287000	287000	321000	341400
Above 60 yrs. but not exceeding 65 yrs.	6	168000	219000	219000	244500	259800
Above 65 yrs.	5	142500	185000	185000	206250	219000
National Income	**51000**	**L.E.+L.A.+F.E.**	**15000**			

* Rs. 5000 shall be added in the above if spouse is alive
* Medical expenses shall be added in the above according to actual expenses incurred before death supported by bills/vouchers but not exceeding Rs 20,000
* **Compensation in case of death on basis of no fault**
  Rs. 1,00,000/-
* No compensation shall be paid if victim was involved in illegal activities like theft of electricity or riots etc.
* Compensation shall be decided within one month from date of the accident by a committee of concerned Superintending Engineer and Executive Engineer

(Law Officer) UPPCL 30/6/18 | (Director(E)) UPPCL | Director(PM&A) UPPCL | (Acting Director) ESO | (Managing Director) MVVNL | (Managing Director) UPPTCL

Compensation in case of permanent disability on basis of fault

AGE OF VICTIM	MULTIPLAIR	Percentge of disability																						
		1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	14%	20%	30%	31%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Up to 15 yrs.	15	17650	25300	32950	40600	48250	55900	63550	71200	78850	86500	94150	101800	117100	163000	239500	247150	316000	392500	469000	545500	622000	698500	775000
Above 15 yrs. but not exceeding 20 yrs.	16	18160	26320	34480	42640	50800	58960	67120	75280	83440	91600	99760	107920	124240	173200	254800	262960	336400	418000	499600	581200	662800	744400	826000
Above 20 yrs. but not exceeding 25 yrs.	17	18670	27340	36010	44680	53350	62020	70690	79360	88030	96700	105370	114040	131380	183400	270100	278770	356800	443500	530200	616900	703600	790300	877000
Above 25 yrs. but not exceeding 30 yrs.	18	19180	28360	37540	46720	55900	65080	74260	83440	92620	101800	110980	120160	138520	193600	285400	294580	377200	469000	560800	652600	744400	836200	928000
Above 30 yrs. but not exceeding 35 yrs.	17	18670	27340	36010	44680	53350	62020	70690	79360	88030	96700	105370	114040	131380	183400	270100	278770	356800	443500	530200	616900	703600	790300	877000
Above 35 yrs. but not exceeding 40 yrs.	16	18160	26320	34480	42640	50800	58960	67120	75280	83440	91600	99760	107920	124240	173200	254800	262960	336400	418000	499600	581200	662800	744400	826000
Above 40 yrs. but not exceeding 45 yrs.	15	17650	25300	32950	40600	48250	55900	63550	71200	78850	86500	94150	101800	117100	163000	239500	247150	316000	392500	469000	545500	622000	698500	775000
Above 45 yrs. but not exceeding 50 yrs.	13	16630	23260	29890	36520	43150	49780	56410	63040	69670	76300	82930	89560	102820	142600	208900	215530	275200	341500	407800	474100	540400	606700	673000
Above 50 yrs. but not exceeding 55 yrs.	11	15610	21220	26830	32440	38050	43660	49270	54880	60490	66100	71710	77320	88540	122200	178300	183910	234400	290500	346600	402700	458800	514900	571000
Above 55 yrs. but not exceeding 60 yrs.	8	14080	18160	22240	26320	30400	34480	38560	42640	46720	50800	54880	58960	67120	91600	132400	136480	173200	214000	254800	295600	336400	377200	418000
Above 60 yrs. but not exceeding 65 yrs.	6	13060	16120	19180	22240	25300	28360	31420	34480	37540	40600	43660	46720	52840	71200	101800	104860	132400	163000	193600	224200	254800	285400	316000
Above 65 yrs.	5	12550	17650	17650	20200	22750	25300	27850	30400	32950	35500	38050	40600	45700	61000	86500	89050	112000	137500	213600	188500	214000	239500	265000
Notional Income	51000			Pain and Suffering for Grievous Injury				10000																

*Medical expenses shall be added in the above according to actual expenses incurred before death supported by bills/vouchers but not exceeding Rs. 20,000.
*Temporery disability- Loss of income, if any, for actual period of disablement not exceeding fifty two weaks.
*Compensation in case of 100% permanent disability on basis of no fault-Rs.1,25,000/- (accordingly compensation may calculated for different percentage of permanant disability)
*Grievous injury- Rs.3000/- and Simple injury Rs. 2000/-
*No compensation shall be paid if victim was involved in illegal activities like theft of electricity or riots etc.
*Compensation shall be decided within one month from date of the accident by a committee of concerned Superintending Engineer and Executive Engineer.
*In deciding percentage of disability certificate of medical board shall be final however schedule I of The Workmen Compensation Act may also be consulted.

(Law Officer) UPPCL Member	Director (F) UPPCL Member	(Director(P M&A)) UPPCL Member/Convener	(Acting Director) ESO Member	(Managing Director) MVVNL Member	(Managing Director) UPPTCL Chairman
30/6/18					

1005531/14

(12)

संख्या बी-3-151/दस-80-15(1)/78-प्र0को0

SC 11

श्री टी0 एन0 दवे,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

ं,

समस्त विभागाध्यक्ष,
तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 24 जनवरी, 1980।

:--मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता।

,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या बी-3-258/दस-15(1)/78, दिनांक 31 जनवरी, 1979 के क्रम में मुझे हने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या बी-3-3249/दस-20(10)/77 दिनांक 3 अक्तूबर, 1978 के साथ उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि के विनियमन हेतु नियमावली के सम्बन्ध में पुनर्विचार करने के उपरान्त शासन ने नियमावली के नियम 1 के नीचे दी गई टिप्पणी को निम्न प्रकार संशोधित करने का निर्णय लिया है:—

वर्तमान टिप्पणी	संशोधित टिप्पणी
द "परिवार" में मृत सरकारी कर्मचारी की केवल वैध सन्तान, पिता और माता सम्मिलित हैं।	शब्द "परिवार" में मृत सरकारी कर्मचारी के निम्नलिखित सम्बन्धियों में से केवल वे ही सम्मिलित माने जायेंगे, जो मृत्यु के समय उस पर पूर्णतया आश्रित थे—पत्नी/पति, वैध सन्तान, सौतेली सन्तान, पिता और माता।

2--शासन ने उक्त निधि से आर्थिक सहायता के लिये पूर्व में निर्धारित प्रार्थना-पत्र के प्रारूप को भी सरली- के उद्देश्य से संशोधित करने का निर्णय लिया है जिसका संशोधित प्रारूप संलग्न है।

संलग्नक—उपर्युक्त प्रकार

भवदीय,
टी० एन० दवे,
उप सचिव।

संख्या बी-3-151 (1)/दस-80-15(1)/78-प्र0को0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:—

(1) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(2) निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
टी० एन० दवे,
उप सचिव।

संख्या बी 3-151(2)/दस-80-15(1)/78-प्र0को0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भी इस अनुरोध सहित प्रेषित : वे कृपया सन्दर्भगत प्रार्थना-पत्र के संशोधित प्रारूप को समुचित संख्या में मुद्रित करके उसकी प्रतियों की आपूर्ति समस्त भागाध्यक्षों/प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को उनकी मांग के अनुसार करने की व्यवस्था करें।

आज्ञा से,
टी० एन० दवे,
उप सचिव।

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या–2018–औस/2012–27–एफ0/80 दिनांक 5 जुलाई, 2012

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकार का अधिसूचना संख्या–6/12/73/कार्मिक–2/2011–टी0सी0–IV, दिनांक 22.12.2011 द्वारा उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (नवॉ संशोधन) नियमावली 2011 के नियम–2 में किये गये संशोधन को अंगीकार किये जाने का पावर कारपोरेशन ने निर्णय लिया है।

उपरोक्त अधिसूचना अंगीकृत किये जाने के फलस्वरूप एतदद्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1975 (यथा संशोधित) के नियम– 2 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड प्रतिस्थापित किया जाता है:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान खण्ड	एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ग) कुटुम्ब के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होगें:–	(ग) कुटुम्ब के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होगें:–
1. पत्नी या पति,	1. पत्नी या पति
2. पुत्र	2. पुत्र/दत्तक पुत्र
3. अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां,	3. अविवाहित पुत्रियां अविवाहित दत्तक पुत्रियां, विधवा पुत्रियां और विधवा पुत्र वधुऐं,
4. मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।	4. मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।
परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिये अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियॉ भी सम्मिलित होगीं।	5. ऐसे लापता सरकारी सेवक, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा 'मृत' के रूप में घोषित किया गया है, के उपरिउल्लिखित सम्बन्धी, परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द"कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियॉ भी सम्मिलित होंगी।

नियमावली के अन्य प्राविधान यथावत् रहेगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,
निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0)

.....2/–

(14)

Hindu Succession Act, 1956

The Hindu Succession Act, 1956 is an Act of the Parliament of India enacted to amend and codify the law relating to intestate or unwilled succession, among Hindus, Buddhists, Jains, and Sikhs.[1] The Act lays down a uniform and comprehensive system of inheritance and succession into one Act. The Hindu woman's limited estate is abolished by the Act. Any property possessed by a Hindu female is to be held by her absolute property and she is given full power to deal with it and dispose it of by will as she likes. Parts of this Act was amended in 2005 by the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005.[2]

Hindu Succession Act, 1956

सत्यमेव जयते

An Act to amend and codify the law relating to intestate succession among Hindus.

Citation	Act 30 of 1956 (http://punjabrevenue.nic.in/hsuccact(1).htm)
Enacted by	Parliament of India
Date enacted	17 June 1956
	Status: In force

Contents

Applicability
- As per religion
- As per tribe

In the case of males

In the case of females

Certain exceptions

Amendment

References

External links

Applicability

As per religion

This Act is applicable to the following:[1]

- any person who is a Hindu by religion in any of its forms or developments including a Virashaiva, a Lingayat or follower of the Brahmo, Prarthana or Arya Samaj;
- any person who is Buddhist, Sikh by religion; and
- to any other person who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion unless it is proved that the concerned person would not have been governed by the Hindu Law or by any custom or usage as part of that law in respect of any of the matters dealt with herein if this Act had not been passed.

Explanation as to who shall be considered as Hindus, Buddhists, Jains or Sikhs by religion has been provided in the section:

- any child, legitimate or illegitimate, both of whose parents are Hindus, Buddhists, Jains or Sikhs by religion;
- any child, legitimate or illegitimate, one of whose parents is a Hindu, Buddhist, Jain or Sikh by religion and who is brought up as a member of the tribe, community, group or family to which such parent belongs or belonged;
- any person who is convert or re-convert to the Hindu, Buddhist, Jain or Sikh religion.

A person shall be treated as a Hindu under the Act though he may not be a Hindu by religion but is, nevertheless, a person to whom this Act applies by virtue of the provisions contained in this section.

As per tribe

However it has been provided that not withstanding the religion of any person as mentioned above, the Act shall not apply to the members of any Scheduled Tribe within the meaning of clause (25) of article 366 of the Constitution of India unless the Central Government, by notification in the *Official Gazette*, otherwise directs. Surajmani Stella Kujur Vs. Durga Charan Hansdah-SC

In the case of males

property of a Hindu male dying intestate, or without a will, would be given first to heirs within Class I. If there are no heirs egoriz as Class I, the property will be given to heirs within Class II. If there are no heirs in Class II, the property will be given to ne deceased's agnates or relatives through male lineage. If there are no agnates or relatives through the male's lineage, then the property is given to the cognates, or any relative through the lineage of females.

There are two classes of heirs that are delineated by the Act.

Class I heirs are sons, daughters, widows, mothers, sons of a pre-deceased son, widows of a pre-deceased son, son of a, pre-deceased sons of a predeceased son, and widows of a pre-deceased son of a predeceased son.

If there is more than one widow, multiple surviving sons or multiples of any of the other heirs listed above, each shall be granted one share of the deceased's property. Also if the widow of a pre-deceased son, the widow of a pre-deceased son of a pre-deceased son or the widow of a brother has remarried, she is not entitled to receive the inheritance.

Class II heirs are categorized as follows and are given the property of the deceased in the following order:

1. Father
2. Son's / daughter's son
3. Son's / daughter's daughter
4. Brother
5. Sister
6. Daughter's / son's son
7. Daughter's / son's daughter
8. Daughter's / daughter's son
9. Daughter's /daughter's daughter
10. Brother's son
11. Sister's son
12. Brother's daughter

In the case of females

Under the Hindu Succession Act, 1956,[1] females are granted ownership of all property acquired either before or after the signing of the Act, abolishing their "limited owner" status. However, it was not until the 2005 Amendment that daughters were allowed equal receipt of property as with sons. This invariably grants females property rights.

The property of a Hindu female dying intestate, or without a will, shall devolve in the following order:

1. upon the sons and daughters (including the children of any pre-deceased son or daughter) and the husband,
2. upon the heirs of the husband.
3. upon the father and mother
4. upon the heirs of the father, and
5. upon the heirs of the mother.

Certain exceptions

Any person who commits murder is disqualified from receiving any form of inheritance from the victim.

If a relative converts from Hinduism, he or she is still eligible for inheritance. The descendants of that converted relative, however, are disqualified from receiving inheritance from their Hindu relatives, unless they have converted back to Hinduism before the death of the relative.

Amendment

The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005,[2] amended Section 4, Section 6, Section 23, Section 24 and Section 30 of the Hindu Succession Act, 1956. It revised rules on coparcenary property, giving daughters of the deceased equal rights with sons, and subjecting them to the same liabilities and disabilities. The amendment essentially furthers equal rights between males and females in the legal system.

References